


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2013/वैशाख 2, 1935

No. 82]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2013/VAISAKHA 2, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं० 01 (आर.ई.-2013)/2009-2014

फा.सं. 18/03/एम-14/पी-5.—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) के अध्याय 5 को अधिसूचित करते हैं। यह अध्याय 18 अप्रैल, 2013 से लागू होगा।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) की निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम संबंधी अध्याय 5 की विषय-वस्तु संलग्न अनुबंध में दी गई है (13 पृष्ठ)।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) की निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम संबंधी अध्याय 5 के संशोधित संस्करण को मौजूदा स्कीम के दो संस्करणों को सुसंगत किए जाने के पश्चात् तत्काल प्रभाव से मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अध्याय - 5**निर्यात संवर्धन पजीगत माल (ई. पी. सी. जी.) स्कीम**

- 5.1** **नीति** विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 में शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम से संबंधित नीति दी गई है।
- 5.2** **आवेदन प्रपत्र** प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन, आयात-निर्यात प्रपत्र 5क में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
वार्षिक आवश्यकता के लिए प्राधिकार-पत्र ईपीसीजी स्कीम के अन्य प्रावधानों और शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगा:-
- 5.2क** **वार्षिक आवश्यकता के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र** (क) प्राधिकार पत्र विशिष्ट शुल्क से बचाई गई राशि और संगत निर्यात दायित्व के साथ जारी किया जाएगा। आवेदक को प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्यात उत्पाद निर्दिष्ट करने होंगे।
(ख) प्राधिकार पत्र धारक को आयातित पूँजीगत माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को, परिशिष्ट-32क में स्वतन्त्र सनदी अभियन्ता (सीईसी) से अन्तरसंबंध प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सीईसी की एक प्रति पूँजीगत माल के आयात की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रविष्टि बिल की प्रति सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
- 5.3** **अंतरसंबंध प्रमाणीकरण** (क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 32क में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी अभियन्ता (सीईसी) से अन्तरसंबंध प्रमाण पत्र के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र जारी करेगा। उपयुक्त अपशिष्ट, यदि कोई हो, पूँजीगत माल के अधिष्ठापन के समय भी नेक्सस प्रमाण-पत्र में चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होगा और इसको जारी करने के समय ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की कन्डीशन शीट में इसका उल्लेख किया जाएगा।
(ख) इसके पश्चात क्षेत्रीय प्राधिकारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। प्राधिकार पत्र को जारी करने के समय अनुमत अपशिष्ट को स्कैप/अपशिष्ट की बिक्री पर लागूशुल्क के भुगतान पर बेचने की अनुमति होगी।
- 5.3.1** (क) प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयात पूरा करने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पूँजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं)/विक्रेता(विक्रेताओं) की फैक्टरी/परिसर में अधिष्ठापित कर दिया गया है।
(ख) कल पुर्जों के आयात के मामले में, अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्राधिकार पत्र धारक द्वारा जमा किया जाएगा।
(ग) तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास गैर-पंजीकृत यूनितों के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को, एक स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा पूँजीगत वस्तुओं/ कल-पुर्जों की अधिष्ठापना सुनिश्चित करने के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

5.3.2

आयातों के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 4.19 में निर्दिष्ट एक मात्र पूंजीकरण पत्तन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, पैराग्राफ 4.19 में विनिर्दिष्ट किसी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है।

5.3.3

(क) आवेदक पूंजीगत माल के रख-रखाव और अधिष्ठापन के लिए आवश्यक स्पेयर्स, टूल्स, रिफ्रैक्टरीज़ और कैटालिस्ट के आयात के लिए भी आवेदन कर सकता है। आवेदन में, सनदी अभियंता अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित, आवेदक की फ़ैक्टरी/परिसर में अधिष्ठापित संयंत्र/मशीनरी की सूची संलग्न होनी चाहिए, जिसके लिए स्पेयर्स, टूल्स, रिफ्रैक्टरीज़ और कैटालिस्ट की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र स्पेयर्स की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगा:

(i) संयंत्र/मशीनरी का नाम जिसके लिए स्पेयर्स की आवश्यकता है।

(ii) प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य।

(iii) विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात दायित्व के मूल्य सहित निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण।

(ख) इसके अलावा, निर्यात दायित्व की अन्तिम रूप से विमुक्ति के समय, प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा रखे गए स्टॉक और खपत रजिस्टर के आधार पर अधिष्ठापित पूंजीगत वस्तुओं में इस प्रकार आयातित स्पेयर्स, टूल्स, रिफ्रैक्टरीज़ और कैटालिस्ट का प्रयोग किया गया है।

(ग) यदि विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.2क के तहत आवेदन किया गया है तो अलग प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

5.4

ईओयू/पुनर्स्थापित एस ई जैड यूनिटों को परिणामी डी टी ए यूनिट में परिवर्तन हेतु ई.पी.सी.जी. स्कीम

ई.ओ.यू/पुनर्स्थापित एस.ई.जैड एकक, डी टी ए यूनिट में परिवर्तन करते समय ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। संबंधित विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

5.5

पूंजीगत माल की स्वदेशी स्रोतों से प्राप्ति

(क) स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक, सीधे आयात के लिए/ए आर ओ जारी करने के लिए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र को अमान्य कराने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध भेजेंगे।

(ख) यह अनुरोध आवेदन पत्र सहित अथवा ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद किया जा सकता है।

(ग) आवेदक उस व्यक्ति का नाम और पता भी देगा जिससे वह पूंजीगत माल प्राप्त करना चाहता है।

- 5.5.1** संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसा अवैधीकरण पत्र/अग्रिम विमुक्ति आदेश दो प्रतियों में जारी करेगा ।
- 5.5.2** ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, ट्टायात-निर्यात प्रपत्र। में क्षेत्रीय प्राधिकारी को, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए यथा अपेक्षित ऐसी निविदियों के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
- 5.6 लीज के आधार पर स्वदेशी पूंजीगत माल को प्राप्त करना पूंजीगत माल को पट्टे पर देना** ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक, पूंजीगत माल को घरेलू लीजिंग कम्पनी से प्राप्त करेगा । ऐसे मामलों में, आयातित पूंजीगत माल का प्रविष्टि बिल या स्वदेशी स्म से प्राप्त वाणिज्यिक बीजक, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक और लीजिंग कम्पनी द्वारा संयुक्त स्म से हस्ताक्षरित होंगे । तथापि, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।
- 5.7 निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्त** विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:—
- 5.7.1** (क) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक या तो सीधा निर्यात अथवा तीसरी पार्टी (पार्टियों) के माध्यम से निर्यात करेगा । यदि व्यापारी निर्यातक, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक है तो सहायक विनिर्माता का नाम पोतलदान बिल में भी दर्शाया जाएगा।
(ख) निर्यात के समय, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र सं. और तारीख पोतलदान बिल पर पृष्ठांकित की जाएगी, जिसे निर्यात दायित्व के निष्पादन के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।
- 5.7.2** मान्य निर्यातों के अलावा निर्यात आय, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी । वसूली की मुद्रा चाहे जो भी हो, एसईजेड यूनिटों को निर्यात/विकासक/सह-विकासकों को की गई आपूर्तियों को भी निर्यात में गिना जाएगा।
- 5.7.3** तेल और गैस क्षेत्र को की गई आपूर्तियों को ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा किया गया समझा जाएगा बशर्ते कि इसे 31.3.2000 को या उससे पहले जारी किया गया हो और ऐसी आपूर्तियों के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत कोई लाभ का दावा न किया गया हो ।
- 5.7.4** औसत निर्यात दायित्व की गणना करते समय, निम्नलिखित प्रकार के निर्यातों को गिनती में नहीं लिया जाएगा, भले ही वे पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए हों:
(i) ऐसे देशों को निर्यात, जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय ने समय-समय पर इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया हो;
(ii) वैध निर्यात दायित्व अवधि के भीतर ईपीसीजी प्राधिकार-पत्रों के संबंध

में विशिष्ट निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए गिने जा रहे निर्यात (चाहे अवधि-मूल अवधि हो या बढ़ाई गई)।

5.7.5

ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत किए गए निर्यात, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 के तहत लाभों के भी हकदार होंगे।

5.7.6

(क) निम्न से संबंधित निर्यात के मामले में:

- (i) हस्तशिल्प,
- (ii) हथकरघा,
- (iii) कुटीर व अत्यन्त छोटे उद्योग,
- (iv) कृषि
- (v) जल कृषि (मत्स्य क्षेत्र सहित), मत्स्योद्योग,
- (vi) पशु-पालन,
- (vii) पुष्पोत्पादन व बागवानी,
- (viii) मुर्गी पालन,
- (ix) अंगुरोत्पादन,
- (x) रेशमोत्पाद,
- (xi) कालीन,
- (xii) कॉयर और
- (xiii) जूट

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) तथापि, निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने से यह छूट मछली पकड़ने के ट्रॉलर्स, नौका, पोत, और अन्य ऐसी ही मदों के आयात के लिए अनुमत नहीं होगी।

(ग) ऊपर उप पैरा- (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित औजारों को छोड़कर, माल को, आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे मामलों में भी जहाँ निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद समूह कम्पनियों को पूंजीगत माल के हस्तांतरण की अनुमति आयात की तारीख से पांच वर्ष के भीतर दी जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को दी जाएगी।

5.8

निर्यात दायित्व पूरा करने के ब्लॉक

ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारक निम्नलिखित अनुपात में निर्यात दायित्वों को विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा करेगा:

प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से अवधि	पूरा किया जाने वाला न्यूनतम निर्यात दायित्व
1 से 4 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
5 और 6 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

5.8.1

तथापि, किसी वर्ष के विशेष ब्लॉक में निर्यात दायित्व पहले के ब्लॉक वर्षों में किए गए अधिक निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व पूरा करने पर तथा साथ में डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा ब्लॉक के पूरा होने के तीन महीने के भीतर औसत निर्यातों को सूचित करेगा।

5.8.2

जहाँ उपर्युक्त अनुपातों के अनुसार प्रथम ब्लॉक का निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जाता (सिवाए ऐसे मामलों के, जहाँ निर्यात दायित्व के पूरे न किए गए भाग के बराबर बचाई गई शुल्क राशि पर 2 प्रतिशत कंपोजिशन शुल्क अदा करने की शर्त के अधधीन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम ब्लॉक के लिए विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व बढ़ाया गया हो), ऐसा प्राधिकार धारक ब्लॉक की अवधि बीत जाने के 3 माह के भीतर, पूरे न किए गए निर्यात दायित्व पर बचाई गई शुल्क राशि के अनुपात में सीमा-शुल्क का भुगतान करेगा (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज के साथ)।

5.8.3

(क) 31.3.2000 तक जारी किए गए ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर.ई-99) के पैराग्राफ 6.11 में दिए गए प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर.ई-99) में निहित प्रावधानों के बावजूद के मूल्यवार कमी के मामले में प्राधिकार पत्र धारक को विशेष आयात लाइसेंस वापिस नहीं करना होगा।

(ख) 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2002 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-01) के अध्याय-6 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(ग) 1 अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(घ) 1 सितंबर, 2004 से 17 अप्रैल, 2013 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र 17.04.2013 तक यथा-संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (संशोधित संस्करण-12) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

5.9**निर्यात दायित्व की निगरानी**

प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व को पूरा करने में की गई रिपोर्ट के बारे में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी आंशिक निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा बशर्ते कि निर्यात निष्पादन अनुपातिक रूप से निर्यात दायित्व के पूरा होने से पर्याप्त हो।

5.10

**10 प्रतिशत सी आई एफ
मूल्य तक स्वचालित कमी/
वृद्धि और निर्यात दायित्व में
यथानुपात कमी/वृद्धि**

(क) यदि जारी किए गए प्राधिकार पत्र का आधिक्य में किसी मूल्य के आयात के लिए वास्तविक रूप से उपयोग कर लिया गया है, जो सीआईएफ मूल्य/प्राधिकार के बचाए गए शुल्क के 10 प्रतिशत तक हो, तो प्राधिकार को यथा-अनुपात में बढ़ा दिया गया माना जायेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के मूल्य/बचत की गई राशि के 10 प्रतिशत तक, अधिक माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा।

(ख) ऐसे मामलों में, प्राधिकार-पत्र धारक सीआईएफ मूल्य/बचाई गई शुल्क राशि के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को मूल्य में आयातों के एक महीने के भीतर, किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वयं अनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।

(ग) उपयोग के 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पृष्ठांकित कर सकता है। प्राधिकार पत्र धारक सीमाशुल्क प्राधिकारी को अतिरिक्त बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

5.10.1

इसी प्रकार, यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक ने प्राधिकार पत्र में दिए गए मूल्य से कम प्राधिकार पत्र का प्रयोग किया है, तो उसका निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा।

5.11

**निर्यात दायित्व अवधि में
विस्तार**

(क) 17.04.2013 तक जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार-पत्रों के मामले में (शून्य शुल्क ईपीसीजी को छोड़कर), संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र के तहत लागू कुल निर्यात दायित्व के 10 प्रतिशत तक लागू निर्यात दायित्व में वृद्धि अथवा पूरे न किए गए निर्यात दायित्व के तहत बचाये गये कुल शुल्क के 2 प्रतिशत के संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की मंजूरी हेतु एक अथवा अधिक जैसा भी मामला हो, आवेदनों पर विचार कर सकता है, यह माँगे गये विस्तार के प्रत्येक वर्ष हेतु निर्यातक की इच्छा पर आधारित होगा। निर्यात दायित्व अवधि में ऐसा पहला विस्तार 2 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए हो सकता है।

(ख) ऊपर उपलब्ध 2 वर्षों से अधिक की अवधि हेतु निर्यात दायित्व विस्तार पर आगे दो वर्षों तक के विस्तार विचार किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ई पी सी जी प्राधिकार पत्र पर विस्तार संबंधी पृष्ठांकन करने से पूर्व, प्राधिकार पत्र धारक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में भुगतान किए जाने वाले शुल्क का 50% भुगतान कर दिया हो। ऐसे मामलों में, संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा या अतिरिक्त निर्यात दायित्व नहीं लगाया जाएगा जैसा कि ऊपर के पैरे में विनिर्दिष्ट है। यदि फर्म अब भी निर्यात दायित्व पूरा नहीं पाती है तो पहले से जमा किए शुल्क को कुल शुल्क और निर्यात दायित्व में चूक करने के लिए दिये जाने वाले ब्याज में से काट लिया जाएगा।

(ग) तथापि, शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार-पत्रों के लिए, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा, निर्यातक की इच्छा पर पूरा न किए गए निर्यात दायित्व पर 2 प्रतिशत के समानुपाती बचाए गए शुल्क की राशि के बराबर समयोजन शुल्क की अदायगी पर अथवा प्राधिकार-पत्र के तहत लगाए कुल निर्यात दायित्व के 10 प्रतिशत की सीमा तक लगाए गए निर्यात दायित्व की बढ़ोतरी पर, जैसा मामला हो, निर्यात दायित्व में 2 वर्षों के केवल एक विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

(घ) मूल निर्यात दायित्व अवधि के समापन की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार के लिए आवेदन किया जाएगा।

(ड.) निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार उन शर्तों के तहत किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

5.11.1

(क) जो फर्म/कम्पनी बी आई एफ आर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर रही है, संबंधित एजेन्सी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए छूट के संबंध में, यदि कोई हो, महानिदेशक, विदेश व्यापार को भी सूचित करेगी।

(ख) उसके बाद महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसी फर्म/कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर लगाए गए निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के संबंध में संबंधित एजेन्सी से सरकार के हितों की रक्षा के मामले पर विचार करेंगे।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशक, 09 वर्ष तक के विस्तार की अवधि की मंजूरी के लिए अथवा संचालन एजेंसी द्वारा तैयार और बी एफ आई आर बोर्ड/ राज्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार कर सकते हैं।

5.11.2

(क) उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहाँ उस क्षेत्र/उत्पाद समूह का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5% से अधिक कम हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध वर्ष में उस विशेष क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातों के समानुपात में वर्ष के लिए औसत निर्यात दायित्व को कम किया जा सकता है। तथापि, यदि निर्यात में क्रमागत वर्षों में लगातार कमी जारी रहती है, तो औसत निर्यात दायित्व में पात्रता की गणना और कमी की गणना का आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा, जिसके बाद निर्यातों में लगातार कमी आई है।

(ख) क्षेत्रों/उत्पाद समूहों जिनके लिए इस छूट की अनुमति दी जानी है, पिछले वित्तीय वर्ष समाप्त होने के सात महीनों के अंदर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा और तदनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी उस क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातकों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण करेंगे।

5.11.3

निर्यात उत्पाद पर रोक के

जहाँ किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे निर्यात उत्पादों से पूर्व पहले से जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के सम्बंध में निर्यात

**मामले में स्वतः निर्यात
दायित्व विस्तार**

दायित्व अवधि, बिना किसी संयोजक शुल्क के, रोक की अवधि के बराबर अवधि के लिए स्वतः बढ़ी हुई मानी जाएगी और निर्यातक को रोक की अवधि के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

**5.12
निर्यात दायित्व में कमी**

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, बचाए गए शुल्क की राशि से उत्पन्न कारण निर्यात दायित्व (विशिष्ट निर्यात दायित्व) में 5 प्रतिशत तक की कमी को माफ कर सकता है।

**5.13
विमुक्ति**

(क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रूप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात-निर्यात फार्म 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आवेदन 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएँ। यदि कोई कमी है तो उसे एक बार में दिखाया जायेगा। उसके बाद सभी पत्राचार, सिर्फ उन कमियों के बारे में होंगे। यदि आवश्यक हुआ तो नया पत्राचार 15 दिनों के भीतर किया जाए। एक बार दस्तावेज पूरे हो जाने पर सभी दस्तावेजों/सूचनाओं के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा।

(घ) अन्तिम निष्पादन प्रमाणपत्र/अस्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया, प्रारम्भिक आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जो आवेदन 90 दिन की अवधि के बाद भी बकाया है उनकी सूचना कारणों सहित डी.जी.एफ.टी. को तत्काल दी जाएगी।

**5.14
वास्तविक चूक को
नियमित करना**

(क) यदि ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमाशुल्क तथा ब्याज का भुगतान करेगा। ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक के पास अपनी मर्जी से बाहर होने का विकल्प रहेगा। प्राधिकार पत्र धारक के पास सीमाशुल्क संघटक के भुगतान के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और डीईपीबी प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

**5.15
लेखों का रख-रखाव**

प्रत्येक ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्यात/की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं का सही और उचित लेखा रखेगा।

**5.16
ईपीसीजी स्कीम के तहत
आयातित पूंजीगत माल का
पुनः निर्यात**

ई.पी.सी.जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के काबिल नहीं पाया गया उसे आयात पर शुल्क के भुगतान की तारीख से 3 वर्षों के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को पुनः निर्यात कर सकते हैं जिसकी अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी से लेनी होगी। परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा।

- 5.16.1**
पूँजीगत माल का
प्रतिस्थापन
- आयातित और खराब पाया गया अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु उपयुक्त न पाये गये पूँजीगत माल का निर्यात किया जा सकता है तथा ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत इसके बदले में पूँजीगत माल का आयात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को ऐसे प्रतिस्थापित पूँजीगत माल को आयात के समय पुनः घटा दिया जाएगा।
- 5.17**
दण्डात्मक कार्यवाही
- निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं विदेश व्यापार नीति तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
- 5.18**
ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों
की क्लबिंग
- उसी प्राधिकार पत्र धारक को 18.04.2013 से निर्गमित दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी।
- 5.18.1**
- क्लबिंग के लिए आवेदन 'आयात-निर्यात प्रपत्र' 5घ में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के मामले में क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 5.18.2**
- कुल निर्यात दायित्व, बचाए गए कुल शुल्क को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाएगा।
- 5.18.3**
- क्लबिंग करने पर, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा। क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए निर्यात दायित्व अवधि पहले प्राधिकार पत्र को जारी करने की तारीख से मानी जाएगी।
- 5.18.4**
- क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा।
- 5.18.5**
- निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी।
- 5.18.6**
- ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की क्लबिंग के लिए उपर्युक्त शर्तें 18.04.2013 को या उसके बाद जारी प्राधिकार-पत्र पर लागू होंगी। तथापि, 1.4.2007 से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2006) के अध्याय 5 में निहित शर्तों द्वारा अधिशासित होंगे। 01.04.2007 और 17.04.2013 के दौरान जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय 5 में निहित प्रावधानों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे (आर.ई-2012)।
- 5.19**
पूँजीगत माल का
- पूँजीगत माल के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए आवेदन आयात-निर्यात प्रपत्र 5क में किया जाएगा।

प्रौद्योगिकीय उन्नयन

5.20

रिफर्बिश्ड/रिकंडीशंड पुर्जों
और औज़ारों का आयात

(क) रिफर्बिश्ड/रिकंडीशंड पुर्जों के आयात की शेष अवधि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्रमाणित मूल पुर्जों की कालावधि से 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित औजार आवेदक की समूह कंपनियों या किसी भी एकक को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

5.21

ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के पुनःवैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

5.22

पश्च निर्यात ईपीसीजी
शुल्क क्रेडिट स्क्रिप
(स्क्रिप्स)

(क) निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-5क में एक आवेदन-पत्र दायर करते हुए इस योजना के लिए विकल्प चुनते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) पूंजीगत माल को आयात करने के लिए निर्यातक द्वारा सभी लागू शुल्क नकद में चुकाए जाएंगे।

(ग) निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार-पत्र जारी करेगा:-

(i) प्राधिकार-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 'आयात के लिए' नहीं दर्शाना।

(ii) औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई है।

(iii) गणना किए गए लागू विशिष्ट निर्यात दायित्व के 85% की दर पर विशिष्ट निर्यात दायित्व जैसे कि आयातों को शुल्क छूट का लाभ उठाना था।

(iv) निर्यात दायित्व अवधि जो प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि से लागू होगी।

(घ) निर्यातक विशिष्ट निर्यात दायित्व अवधि के अंदर पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) को जारी करने के लिए आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल ऐसे पहले आवेदन के लिए पूंजीगत माल, (सेनवेट किए शुल्क का प्रमाण अथवा अन्यथा सहित) अन्तर संबंध और स्थापन प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्रों) पर वास्तविक शुल्क अदायगी का प्रमाण को निर्यात दायित्व के पूरा करने के प्रमाण के साथ सौंपा जाएगा। तदन्तर, केवल अतिरिक्त रूप से पूरा किए गए निर्यात दायित्व के पूरा किए जाने का प्रमाण विशिष्ट निर्धारित किए निर्यात दायित्व (उपरोक्त ग (iii) जैसा) को सौंपा जा सकता है जब तक कि पहले सौंपे गए दस्तावेजों/प्रमाणों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात के बराबर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) जारी करेगा।

(च) मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) की गणना अदा किए गए मूल सीमाशुल्क पर आधारित होगा।

(छ) यदि निर्यातक ने प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.22 के अंतर्गत ईपीसीजी का प्राधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है जिसमें घोषित किया गया है कि वह सेनवेट क्रेडिट नहीं प्राप्त करेगा, तो निर्यात दायित्व का भुगतान किए गए मूल सीमाशुल्क के अनुसार निर्धारण किया जाएगा। ऐसे मामलों में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप केन्द्रीय आबकारी विभाग से प्राप्त सेनवेट क्रेडिट प्राप्त

नहीं किया है इस आशय के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जाएंगी। सेनवेट क्रेडिट प्राप्त न करने के संबंध में केन्द्रीय आबकारी विभाग से ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा जहां इकाई केन्द्रीय आबकारी विभाग में पंजीकृत नहीं है।

(ज) मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान लागू रहेंगे जब तक कि वे इस स्कीम के अनुसरण में न हों।

(झ) एफटीपी के पैरा 5.11 के अंतर्गत आयात किए गए पूंजीगत माल का ऐसे पूंजीगत माल के लिए निर्यात दायित्व के प्रतिकरण हेतु किए गए अंतिम निर्यात की तिथि तक निपटान नहीं किया जाएगा।

(ञ) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए पूंजीगत माल के पुनः निर्यात के मामले में यदि निर्यातक इन पुनः निर्यातों पर भुगतान किए गए शुल्क को वापस लेने का दावा प्रस्तुत करता है तो विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.11 के तहत शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

5.23

हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 के तहत शामिल किए गए निर्यात उत्पाद निम्न हैं:

(i) सौर ऊर्जा गैर-केन्द्रीकृत के लिए उपस्कर और ग्रिड से जुड़े

हुए उत्पाद,

(ii) बायो-मास गैसीफायर,

(iii) बायोमास/अपशिष्ट बायलर

(iv) वैपर एबजोरप्शन चिलर्स,

(v) वेस्ट हीट बायलर,

(vi) वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटें,

(vii) अनफायर्ड हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स,

(viii) विंड टरबाईन,

(ix) सोलर कलेक्टर और उसके हिस्से,

(x) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स,

(xi) विंड मिल, विंड टरबाईन/इंजिन,

(xii) अन्य जनरेटिंग सैट्स - विंड पावर्ड,

(xiii) इलैक्ट्रीकली आपरेटिड व्हीकल्स-मोटर कारें,

(xiv) इलैक्ट्रीकली आपरेटिड व्हीकल्स-लारिज एंड ट्रक्स,

(xv) इलैक्ट्रीकली आपरेटिड व्हीकल्स- मोटर साइकिल्स/मोपेड्स और

(xvi) सोलर सैल्स।

(ख) आवेदन आयात-निर्यात प्रपत्र-5क में भरकर प्रस्तुत किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 18th April, 2013

No.01(RE-2013)/ 2009-2014

F.No. 18/03/AM-14/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby notifies Chapter 5 of the Handbook of Procedures (Volume I). This shall come into force from 18th April, 2013.

The text of Chapter 5 pertaining to Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme of Handbook of Procedure (Volume I) is annexed (13 pages).

Effect of this Public Notice:

The revised edition of Chapter 5 pertaining to Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme of the Hand Book of Procedure (Volume I) after harmonizing the two variants of the existing scheme shall replace the existing Procedure with immediate effect.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Annexure**CHAPTER 5****EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS (EPCG) SCHEME**

- | | |
|---|---|
| 5.1
Policy | Policy relating to Zero Duty EPCG Scheme is given in Chapter 5 of FTP. |
| 5.2
Application
Form | An application for grant of an authorization should be made to RA concerned in ANF 5A along with documents prescribed therein. |
| 5.2A
EPCG
Authorization
for Annual
Requirement | <p>The Authorization for Annual Requirement will be issued subject to the following conditions in addition to other terms and conditions governing the EPCG scheme:-</p> <p>(a) Authorizations shall be issued with a specific duty saved amount and corresponding export obligation. The applicant would be required to indicate export products proposed to be exported under the authorization.</p> <p>(b) The authorization holder shall also be required to submit a Nexus Certificate from an independent Chartered Engineer (CEC) in Appendix 32A, to the Customs authorities at the time of clearance of imported capital goods. A copy of the CEC shall be submitted to the concerned Regional Authority alongwith copy of the bill of entry, within 30 days from the date of import of the Capital Goods.</p> |
| 5.3
Nexus
Certification | <p>(a) RA concerned shall, on the basis of nexus certificate from an Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Appendix 32A, issue EPCG authorization. Reasonable wastage, if any, anticipated at the time of installation of capital goods will also be certified by the Chartered Engineer in the nexus certificate and the same would be mentioned in the condition sheet of the EPCG</p> |

authorization at the time of issue.

(b) RA shall thereafter forward a copy of the EPCG authorization to the concerned Jurisdictional Central Excise Authority. The wastage so permitted at the time of issuance of authorization would be allowed to be sold on payment of applicable duty on sale of scrap/ waste.

5.3.1

(a) Authorization holder shall produce to the concerned RA a certificate from the Jurisdictional Central Excise Authority, confirming installation of Capital Goods at factory/ premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s)/ vendor(s) within six months from date of completion of import.

(b) In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorization holder within a period of three years from the date of import.

(c) However, in case of units not registered with Central Excise Authorities, the Authorization holder shall produce to the concerned RA, a certificate from an independent Chartered Engineer confirming the said installation of Capital goods/spares.

5.3.2

EPCG authorization shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of HBP Vol. I for imports. However, exports can be made from any port specified in paragraph 4.19.

5.3.3

(a) An applicant may also apply for import of spares, tools, spare refractories and catalyst as are required for installation and maintenance of Capital Goods. Application shall contain list of plant/ machinery installed in factory/ premises of applicant for which spares, tools, spare refractories and catalyst are required, duly certified by Chartered Engineer or Jurisdictional Central Excise Authorities. In such cases EPCG authorization shall not specify list of spares but shall indicate:

- (i) Name of plant /machinery for which spares are required.
- (ii) Value of duty saved allowed under the authorization.
- (iii) Description of product to be exported with value of export obligation as per FTP.

(b) Further, at time of final redemption of export obligation, authorization holder shall submit certificate from Independent Chartered Engineer confirming use of spares, tools, spare refractories and catalyst so imported in the installed capital goods on the basis of stock & consumption register maintained by authorization holder.

(c) Separate Authorisation shall be issued in case application is filed under Para 5.2A of FTP.

5.4

EPCG Scheme

An EOU/ a relocated SEZ unit, while converting to a DTA Unit, may apply for an EPCG authorization in ANF alongwith documents prescribed therein. 'No Objection Certificate'

for conversion of EOU/Relocated SEZ Units to DTA Unit should be produced from concerned Development Commissioner.

5.5 (a) EPCG authorization holder intending to source capital goods indigenously shall request to RA for invalidating EPCG authorization for direct import / Issuance of ARO.

Indigenous Sourcing of Capital Goods

(b) This request can be made either alongwith application or after issuance of EPCG authorization.

(c) Applicant shall give the name and address of the source person of the capital goods.

5.5.1 RA concerned will issue such invalidation letter/ARO, in duplicate.

5.5.2 Indigenous manufacturer intending to supply capital goods to EPCG authorization holder may apply to RA in ANF for issuance of Advance authorization for import of inputs including components required for manufacture of capital goods to be supplied to EPCG authorization holder.

5.6 An EPCG authorization holder may, source capital goods from a domestic leasing company. In such cases, the Bill of Entry of imported capital goods or commercial invoice of indigenous capital goods, shall be signed jointly by EPCG authorization holder and leasing company. However, EPCG authorization holder shall alone be fully responsible for fulfilment of export obligation.

5.7 In addition to conditions mentioned in paragraph 5.5 of FTP, following conditions shall also be applicable for fulfilment of export obligation:

5.7.1 (a) EPCG authorization holder shall export either directly or through third party(ies). If a merchant exporter is EPCG authorization holder, name of supporting manufacturer shall also be indicated on shipping bills.

(b) At the time of export, EPCG authorization number and date shall be endorsed on shipping bills which are proposed to be presented towards discharge of export obligation.

5.7.2 Export proceeds shall be realized in freely convertible currency except for deemed exports. Exports to SEZ units/ Supplies to developers/ Co-developers, irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of Export Obligation.

5.7.3 Supplies made to Oil and Gas sector also may be counted towards discharge of export obligation against an EPCG authorization provided it has been issued on or before 31.03.2000 and no benefit under paragraph 8.3 of FTP has been claimed on such supplies.

5.7.4

While calculating Average Export Obligation, following types of exports even if made in the preceding 3 years will not be taken into account:

- (i) Exports to such country as may have been notified by DGFT for this purpose from time to time;
- (ii) Exports being counted for fulfilling specific EO in respect of EPCG Authorizations within valid EO Period (whether original or extended).

5.7.5

Export under EPCG scheme shall also be entitled for benefits under Chapter 4 of FTP.

5.7.6

(a) In case of export of goods relating to:

- (i) Handicraft,
- (ii) Handlooms,
- (iii) Cottage & Tiny sector,
- (iv) Agriculture,
- (v) Aqua-culture (including Fisheries), Pisciculture,
- (vi) Animal husbandry,
- (vii) Floriculture & Horticulture,
- (viii) Poultry,
- (ix) Viticulture,
- (x) Sericulture,
- (xi) Carpets,
- (xii) Coir, and
- (xiii) Jute

the EPCG authorization holders shall not be required to maintain average level of exports.

(b) However, this exemption from maintenance of average level of exports shall not be allowed for import of fishing trawlers, boats, ships and other similar items.

(c) Goods, excepting tools imported under EPCG scheme by sectors specified in sub-para (a) above, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. However, transfer of capital goods to group companies, within five years from the date of import would be permitted after fulfilment of EO, under intimation to RA and jurisdictional Central Excise Authority.

5.8

The Authorization holder under the EPCG scheme shall fulfill the export obligation over the specified period in the following proportions:

EO fulfilment blocks

Period from the date of issue of Authorization	Minimum export obligation to be fulfilled
Block of 1st to 4th year	50%
Block of 5th and 6th year	50%

5.8.1

However, the EO of a particular block of year may be set off by the excess exports made in the preceding block year. The Authorization holder would intimate the regional authority on the fulfilment of the export obligation, as well as average

exports, within three months of completion of the block, by secured electronic filing using digital signatures.

5.8.2

Where EO of the first block is not fulfilled in terms of the above proportions, (except in such cases where the EO prescribed for first block is extended by the Regional Authority subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount equal to unfulfilled portion of EO), such Authorization holder shall, within 3 months from the expiry of the block, pay duties of customs (alongwith applicable interest as notified by DOR) proportionate to duty saved amount on unfulfilled EO.

5.8.3

(a) EPCG authorizations issued upto 31.03.2000 shall be governed by provisions laid down in paragraph 6.11 in HBP Vol.1 (RE-99). Notwithstanding the same in HBP Vol. 1 (RE-99), authorization holder shall not have to surrender special Import licence in case of value wise shortfall.

(b) Authorizations issued from 1st April, 2000 upto 31st March, 2002 shall be governed by provisions of Chapter 6 of HBP Vol. 1 (RE-01) as amended from time to time.

(c) Authorizations issued from 1st April, 2002 upto 31st August, 2004 shall be governed by provisions of para 5.8 of HBP Vol. 1 (RE-02) as amended from time to time.

(d) Authorizations issued from 1st September, 2004 upto 17th April, 2013 shall be governed by provisions of para 5.8 of HBP Vol. 1 (RE-12) as amended till 17.04.2013.

5.9

Monitoring of Export Obligation

Authorization holder shall submit to RA concerned by 30th April of every year, report on fulfilment of export obligation. RA concerned may issue partial EO fulfilment certificate, provided export performance is proportionately adequate to fulfilment of export obligation.

5.10

Automatic Reduction/ Enhancement upto 10% of CIF value and prorata Reduction/ Enhancement in export obligation

(a) If authorization issued has actually been utilized for import of a value in excess, upto 10% of CIF value/ duty saved amount of authorization, authorization shall be deemed to have been enhanced by that proportion. Customs shall automatically allow clearance of goods in excess, upto 10% of authorization value/duty saved amount, without endorsement by concerned RA.

(b) In such case, authorization holder shall furnish additional fee to cover excess imports effected, in terms of CIF value/duty saved amount, to RA concerned, within one month of excess imports taking place. Export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.

(c) In case of utilization being more than 10%, concerned RA as per their financial powers, may endorse as per extant provisions. Authorization holder shall furnish additional BG/LUT to the customs authority.

5.10.1

Similarly, if EPCG authorization holder has utilized authorization less than the value earmarked in authorization, his export obligation shall stand reduced on pro-rata basis

5.11
Extension of
Export
Obligation
Period

with reference to actual utilization of authorization.

(a) In respect of EPCG authorizations (other than zero duty EPCG) issued upto 17.4.2013, concerned RA, may consider one or more requests for grant of extension in export obligation period, on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% of total export obligation imposed under authorization, as the case may be, at the choice of exporter, for each year of extension sought. Such first extension in EO period can be for a maximum period of 2 years.

(b) Extension in EO period beyond two years' period available above, may be considered, for a further extension upto 2 years with a condition that 50% of duty payable in proportion to the unfulfilled export obligation is paid by authorization holder to Custom authorities before an endorsement of extension is made on EPCG authorization by RA concerned. In such cases, no composition fee is to be paid or additional EO is to be imposed as prescribed in the Para above. In case the firm is still not able to complete the export obligation, duty already deposited will be deducted from total duty plus interest to be paid for EO default.

(c) However, for zero duty EPCG Authorizations only one extension of 2 years in export obligation period may be considered by concerned RA, on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% of total export obligation imposed under authorization, as the case may be, at the choice of the exporter.

(d) Request for extension in EO Period shall be made to RA within 30 days from the date of expiry of original EO Period.

(e) Extension in export obligation period shall also be subject to such terms and conditions as may be prescribed by competent authority.

5.11.1

(a) The firm /company, while applying for registration with BIFR/Rehabilitation Department of State Government, shall also intimate DGFT with regard to relief sought for EPCG authorization, if any within 30 days of receipt of application by agency concerned.

(b) DGFT, thereafter, shall take up the matter with agency concerned to safeguard government interest on account of default in fulfilment of export obligation imposed on EPCG authorization obtained by such firm/companies.

(c) DGFT may consider request for grant of extension in EOP upto 9 years, or as per rehabilitation package prepared by operating agency and approved by BIFR board/ state authority.

5.11.2

(a) To provide relief to exporters of those sectors where total exports in that sector/product group has declined by more than 5% as compared to the previous year, average export obligation for the year may be reduced proportionate to reduction in exports of that particular sector/product group during the relevant year as against the preceding year. However, in case export decline is continuous over consecutive years, the base year for calculation of eligibility and calculation of reduction in average export obligation will be taken as the year after which the exports have shown continuous decline.

(b) The sectors /product groups for which this relaxation is to be allowed shall be conveyed by the DGFT to all the RAs within seven months of the end of the previous financial year, and the RAs shall re-fix the annual average EO for previous year accordingly, for exporters in that sector / product group.

5.11.3**Automatic EO extension in the event of ban on export product**

Whenever a ban/restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of EPCG authorizations already issued prior to imposition of ban on such export products, would stand automatically extended for a period equivalent to duration of such ban, without any composition fee and exporter would not be required to maintain average E.O. as well for the ban period.

5.12**Export Obligation Shortfall**

RA concerned may condone shortfall upto 5% in export obligation (specific EO) arising out of duty saved amount.

5.13**Redemption**

(a) Authorization holder shall furnish application in ANF 5B with documents prescribed therein as a proof of EO fulfilment.

(b) On being satisfied, RA concerned shall issue a certificate of discharge of export obligation to the EPCG authorization holder and forward a copy to customs authorities with whom BG/LUT has been executed.

(c) RA shall ensure disposal of such applications within 30 days. Shortcomings, if any, shall be pointed out in one go. All correspondence, thereafter, shall relate to these deficiencies only. Fresh correspondence, if necessary, shall be within 15 days. Once documents are complete, EO will be discharged within 30 days of receipt of complete documents /information.

(d) Process of issue of final discharge certificate/ rejection shall be completed within a period of 90 days from date of receipt of initial request. Applications that remain outstanding beyond a period of 90 days shall be reported to DGFT alongwith reasons thereof, immediately thereafter.

5.14

In case, EPCG authorization holder fails to fulfil prescribed

Regularization of Bonafide Default	export obligation, he shall pay Customs Duty along with applicable interest as prescribed by Customs authority. Such facilities can also be availed by EPCG authorization holder to exit at his option. The authorization holder will have the option to furnish valid duty credit scrips, issued under Chapter 3 of FTP, for payment of the customs duty component.
5.15 Maintenance of Records	Every EPCG authorization holder shall maintain, for a period of 3 years from date of redemption, a true and proper account of exports/ supplies made and services rendered towards fulfilment of export obligation.
5.16 Re-Export of Capital Goods Imported under EPCG Scheme	Capital Goods imported under EPCG scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported back to foreign supplier within three years from the date of payment of duty on importation thereof, with permission of RA /Customs Authority. Consequently, EO would be re-fixed.
5.16.1 Replacement of Capital Goods	Capital Goods imported and found defective or otherwise unfit for use may be exported, and Capital Goods in replacement thereof be imported under EPCG scheme. In such cases, while allowing export, the Customs shall credit the duty benefit availed which can be debited again at the time of import of such replaced Capital Goods.
5.17 Penal Action	In case of failure to fulfill export obligation or any other condition of authorization, authorization holder shall be liable for action under FT (D&R) Act, 1992, Orders and Rules made thereunder, provisions of FTP and Customs Act, 1962.
5.18 Clubbing of EPCG authorization	Clubbing of two or more EPCG authorizations issued w.e.f 18.04.2013 to the same authorization holder would be permitted.
5.18.1	An application for clubbing can be made to RA concerned in ANF5D. Clubbing shall not be permitted in case authorizations are issued by different RAs.
5.18.2	Total export obligation would be re-fixed taking into account total of duty saved.
5.18.3	On Clubbing, authorizations for all purpose shall be deemed to be a single EPCG authorization. Export obligation period for clubbed authorization shall be reckoned from first authorization issue-date.
5.18.4	Average export obligation for clubbed authorizations would be highest of average export obligations endorsed on individual authorizations so clubbed.
5.18.5	No clubbing would be permitted after expiry of EOP.
5.18.6	The aforesaid provisions for Clubbing of EPCG Authorizations shall be applicable for authorizations issued on or after 18.04.2013. However, EPCG authorizations issued prior to 1.4.2007 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP Vol.1 (RE-2006). The EPCG Authorizations

issued between 01.04.2007 and 17.04.2013 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP v1 (RE-2012).

5.19

Technological Upgradation of Capital Goods

Application for technological upgradation of the capital goods would be made in ANF5A.

5.20

Import of Refurbished / Reconditioned Spares and Tools

(a) Import of refurbished / reconditioned spares must have a residual life not less than 80% of life of original spare, which would be certified by EPCG authorization holder.

(b) The tools imported under EPCG Scheme may be transferred to any of units or group companies of applicant.

5.21

Revalidation of authorization issued under EPCG scheme shall not be allowed.

5.22

Post Export EPCG Duty Credit Scrip(s)

(a) Exporters can exercise this option by filing an application in ANF5A with the concerned RA, selecting an option for this Scheme.

(b) For importing Capital Goods, all applicable duties shall be paid in cash by the exporter.

(c) RA shall issue an Authorization specifying

(i) "Not for imports" on the body of the Authorization;

(ii) Average EO, if any;

(iii) Specific EO @ 85% of the applicable specific EO, computed as if the imports were to take the benefit of duty exemption; and,

(iv) EOP, which shall commence from the Authorization issue date.

(d) Exporter can file request, in ANF5B, for issuance of Duty Credit Scrip(s) in proportion to the EO completed within the specified EOP. Only for first such application proof of actual duty payments on Capital Goods (including proof of duty CENVATed or otherwise), nexus and installation certificate(s) of Capital Goods shall be submitted alongwith proof of fulfilment of EO. Subsequently, only proof of fulfilment of EO additionally completed vis-à-vis specific EO fixed (as in c(iii) above) may be submitted, unless there has been any changes in documents / proofs submitted earlier.

(e) RA shall issue freely transferable duty credit scrip(s) equivalent to proportionate EO fulfilled.

(f) The computation of freely transferable Duty Credit Scrip(s) will be based on basic customs duty amount paid.

(g) Where the exporter has obtained EPCG authorisation under Para 5.22 (c) of HBP v1, declaring that he shall not avail CENVAT Credit, the Export Obligation shall be fixed with reference to the basic customs duty paid. In such cases Duty Credit Scrip will be issued based on the certificate from Central Excise regarding non-availment of CENVAT credit. Such certificate from central excise regarding non-availing of CENVAT credit will not be

required where the unit is not registered with central excise.

(h) All provisions of the existing EPCG Scheme shall apply insofar as they are not inconsistent with this scheme.

(i) The CG imported under para 5.11 of FTP shall not be disposed of till the date of last export for offsetting EO against such CG.

(j) In case of re-export of CG found defective or unfit for use as per the provisions of para 5.16 of HBPv1 if the exporter claims drawback on such re-export there would be no remission of duty under para 5.11 of FTP

**5.23
Green
Technology
Products**

(a) The Export Products covered under Para 5.10 of FTP are:

- (i) Equipment for Solar Energy decentralized and grid connected products,
- (ii) Bio-Mass Gassifier,
- (iii) Bio-Mass/Waste Boiler,
- (iv) Vapour Absorption Chillers,
- (v) Waste Heat Boiler,
- (vi) Waste Heat Recovery Units,
- (vii) Unfired Heat Recovery Steam Generators,
- (viii) Wind Turbine,
- (ix) Solar Collector and Parts thereof,
- (x) Water Treatment Plants,
- (xi) Wind Mill, Wind Mill Turbine / Engine,
- (xii) Other Generating Sets - Wind powered,
- (xiii) Electrically Operated Vehicles – Motor Cars,
- (xiv) Electrically Operated Vehicles - Lorries and Trucks,
- (xv) Electrically Operated Vehicles – Motor Cycles/Mopeds, and
- (xvi) Solar Cells.

(b) Application shall be filed in ANF5A.